कांग्रेस विधायकों समेत कई कारोबारियो पर आयकर छापे से राजनीति गरमाई

रांची, एजेंसी।

आयकर विभाग ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों प्रदीप यादव तथा जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के रांची, गोड्डा, पटना समेत अन्य स्थानों पर स्थित परिसर और कई कोयला कारोबारियों के परिसर पर एकसाथ छापेमारी की। अंतिम जानकारी मिलने तक छापेमारी जारी है। छापेमारी के साथ ही राज्य की राजनीति एक बार फिर गरमा गयी और सत्ताधारी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे राज्य सरकार को अस्थिर करने और उसे गिराने की साजिश के लिए की गयी कार्रवाई करार दिया। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूछा कि सत्ताधारी पार्टी को जांच से परहेज क्यों है? आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग झारखंड विकास मोर्चा से कांग्रेस में शामिल हुए पोड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव और बेरमो से कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के रांची, गोड्डा और पटना स्थित ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आज तड़के प्रारंभ हुई कार्रवाई अभी भी जारी है। इसके अलावा आयकर विभाग कई कोयला व्यवसाइयों के परिसर पर भी छापेमारी कर रहा है जिसका विवरण अभी नहीं जारी किया गया है।

आयकर छापेमारी पर कांग्रेस ने तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे राज्य सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश का हिस्सा बताया।

हिमाचल चुनाव: कांग्रेस ने एक लाख नौकरियों, पेंशन योजना की बहाली सहित कई वादे किए

प्रियंका गांधी ने कहा, भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूब गया है और 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं

कांगड़ा, एजेंसी।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने पर एक लाख नौकरियां देगी, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगी और प्रत्येक महिला को 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता देगी। वाद्रा ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नशीले पदार्थों की समस्या से भी लड़ेगी, जो युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है तथा हर विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे।

कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूब गया है और 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों का हवाला देते हुए, वाद्रा ने कहा कि उनकी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी अपने वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस एक लाख नौकरियों का सृजन करेगी...छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां बैठे हैं, उन्होंने तीन साल में पांच लाख नौकरियां दी हैं।

राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 1.30 लाख नौकरियां दी हैं। वाद्रा ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में सबसे

कम बेरोजगारी दर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो हिमाचल प्रदेश के युवाओं को एक लाख नौकरियां देने के फैसले को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में अंतिम रूप देगी। उन्होंने कहा, हम यह भी कह रहे हैं कि हम पांच साल में पांच लाख नौकरियां देने की पूरी कोशिश करेंगे। यह हमारी गारंटी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह घर और बाहर काम करने वाली महिलाओं के कंधों पर पड़े बोझ को समझती हैं।

उन्होंने कहा, इसीलिए कांग्रेस हर महिला को 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देना चाहती है। यह 'हर घर लक्ष्मी योजना' के तहत होगी। वाद्रा ने कहा कि इसके अलावा, कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के चार स्कूल बनाना चाहती है और मादक पदार्थ की समस्या से लड़ना चाहती है। वाद्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी लोगों के लिए कुछ नहीं करती और अपने स्वार्थ के लिए काम करती है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में 63,000 सरकारी पद पिछले पांच वर्षों से खाली पड़े हैं और राज्य पर 70,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। कांग्रेस नेता ने कहा, जब हम कहते हैं कि हम एक लाख नौकरियां देंगे, तो उनके (भाजपा) मुख्यमंत्री कहते हैं कि यह संभव नहीं है। लेकिन जब वे देश की संपत्ति, सार्वजनिक उपक्रमों को अपने कारोबारी दोस्तों को बेचना चाहते हैं, तो यह संभव है। वाद्रा ने कहा कि भाजपा का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने कहा, आपने बड़े कारोबारियों का 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है। आपके पास उसके लिए पैसे थे लेकिन कर्मचारी की पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं।

नए संसद भवन का निर्माण कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है: पुरी

कोच्चि, एजेंसी।

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि नए संसद भवन के निर्माण का कार्य बेहद तेज गति से हो रहा है। नए संसद भवन के निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने में एक महीने से भी कम समय बचा है। ज्ञात हो कि सरकार कहती रही है कि परियोजना नवंबर तक पूरी हो जाएगी और संसद का आगामी शीतकालीन सत्र नए भवन में आयोजित किया जाएगा।

चार अगस्त को आवास एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री कौशल किशोर ने लोकसभा में बताया था कि नए संसद भवन के निर्माण की भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत पहुंच गई है और नवंबर का महीना परियोजना को पूरा करने की समय सीमा है। अर्बन

मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) सम्मेलन और प्रदर्शनी– 2022'' का उद्घाटन करने के बाद यहां संवाददाताओं से बातचीत में पुरी ने कहा कि 4,000 से अधिक लोग चौबीसों घंटे इस परियोजना पर काम कर रहे हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या नए संसद भवन का निर्माण निर्धारित समयसीमा के भीतर कर लिया जाएगा, मैं हर सप्ताह निर्माण स्थल का दौरा करता हूं। काम बहुत तेज गति से जारी है। करीब 4,000 लोग चौबीस घंटे काम कर रहे हैं। परियोजना कब पूरी होगी, इसके बारे में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसकी तारीख की घोषणा सरकार पर निर्भर है। उन्होंने दावा किया कि निर्माण कार्य बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। आम तौर पर संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर में आरंभ होता है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में एक नए त्रिकोणीय संसद भवन, एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय, विजय चौक से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर लंबे राजपथ का सुधार, प्रधानमंत्री के एक नए आवास और एक प्रधानमंत्री कार्यालय तथा एक नए उपराष्ट्रपति एन्क्लेव की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिसंबर 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण कार्य टाटा प्रोजक्ट्स लिमिटेड कर रहा है। नए भवन में देश की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल, संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थान होगा।

मुंबई के अस्पताल में मिली 132 साल पुरानी सुरंग

मुंबई,एजेंसी। मुंबई स्थित सरकारी जेजे अस्पताल में 132 साल पुरानी सुरंग मिली है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि ब्रिटिश राज में बनी इस 200 मीटर लंबी सुरंग की आधारशिला पर 1890 की तिथि अंकित है।

अधिकारी ने संवाददाताओं से बताया कि जिस भवन के नीचे यह सुरंग मिली है पहले उसका उपयोग महिलाओं और बच्चों के उपचार के लिए वार्ड के रूप में होता था। अस्पताल परिसर में स्थित इस भवन को बाद में नर्सिंग कॉलेज में बदल दिया गया। अधिकारी ने बताया, पानी लीक होने की शिकायत के बाद हमने नर्सिंग कॉलेज भवन का मुआयना किया।

कृषि को नई दिशा में ले जा रहा उद्योग: धनखड़

चंडीगढ़, एजेंसी।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि किसान उभरते भारत की रीढ़ हैं। इसके साथ ही उन्होंने उद्योग को कृषि क्षेत्र को नयी दिशा दिखाने का श्रेय दिया। धनखड़ ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले के 15वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसे वैश्विक रूप से मान्यता मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसान इस उदय की रीढ़ हैं।

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि कृषि क्षेत्र को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए उद्योग की प्रतिबद्धता सराहनीय है और इसे क्रियान्वयन के उच्च चरण में ले जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने इस मेले के विषय (थीम) – सतत कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के लिए डिजिटल परिवर्तन – को उपयुक्त बताते हुए कहा कि इसकी प्रासंगिकता पर कभी भी अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। धनखड़ ने कहा कि किसानों को अच्छी तरह से जानकारी देने की आवश्यकता है ताकि वे आर्थिक रूप से स्थायी उपायों को अपना सकें। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान पिछले दो साल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार के योगदान की भी सराहना की।

एक नजर

भारत में निवेश, औद्योगिक गठजोड़ बढ़ाना चाहता है ताईवान

नई दिल्ली, एजेंसी। ताईवान ने भारत को विनिर्माण क्षेत्र में विश्व का सर्वोत्तम स्थान बताते हुए भारतीय कंपनियों के साथ निकटता से भारत की मेक इन इंडिया और मेक फॉर ग्लोब नीति के अनुरूप काम करने का इरादा जताया है। भारत ताईवान औद्योगिक गठजोड़ सम्मेलन में भाग लेने आये ताईवान के आर्थिक मामलों के उप मंत्री चेन चर्न च्यी ने यहां इस आयोजन में अपने संबोधन में भारत एवं ताईवान के बीच मुक्त व्यापार समझौते की संभावना के बारे में भी चर्चा की। इसका आयोजन भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य परिसंघ (फिक्की) और ताईवान चाईनीज़ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ (सीएनएफआई) ने मिल कर किया था। चेन ने कहा कि भारत विनिर्माण के लिए विश्व का सर्वोत्तम स्थान हो सकता है। भारत की मेक इन इंडिया नीति ताईवान सरकार की नीति 'न्यू साउथबाउंड पॉलिसी' के अनुरूप है। इस नीति में भारत को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ क्षैतिज गठजोड़ में विश्वास रखतीं हैं ताकि हम स्थानीय लोगों के साथ काम करें और साथ में ही प्रगति करें।

राजनीति में हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है: गहलोत

कोटा,एजेंसी।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना वाजिब है लेकिन फर्क नजरिये का होता है। गहलोत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दो दिन पहले ही पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत की 'बड़ाई' किए जाने पर कटाक्ष करते इसे 'रोचक घटनाक्रम' बताया था और पार्टी आलाकमान से राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर 'अनिर्णय' की स्थिति को समाप्त करने को कहा था।

पार्टी में आंतरिक चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर गहलोत ने बारां

में बिना किसी का नाम लिए संवाददाताओं से कहा, राजनीति में हर किसी की थोड़ी-बहुत महत्वाकांक्षा होती है और होनी भी चाहिए है। यह नजरिया है जिससे फर्क पड़ता है। सत्ताधारी दल में आंतरिक कलह का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस पर और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं और कहा कि राज्य और देश के हित में राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी है।

ईडी ने शब्बीर शाह के घर को कुर्क किया

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि उसने केंद्रशासित प्रदेश में आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का श्रीनगर स्थित आवास कुर्क कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 21.80 लाख रुपये कीमत का यह घर श्रीनगर के बरजुल्ला थाना क्षेत्र के सनत नगर की बोत्शाह कॉलोनी में स्थित है। शाह के खिलाफ धनशोधन का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा मई 2017 में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के प्रमुख हाफिज़ सईद और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी से उपजा है।

मंत्री ने कहा कि कृषि अनुसंधान निकाय आईसीएआर द्वारा विकसित 'पूसा डीकंपोजर' पराली जलाने की समस्या से निपटने के

पराली जलाना 'राजनीतिक मुद्दा' नहीं: तोमर

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब समेत उत्तर भारत के चार प्रमुख राज्यों में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर शुक्रवार को चिंता व्यक्त करते हुए राज्यों से इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की अपील की। मंत्री ने कहा कि 2018 से केंद्र सरकार ने राज्यों को पराली जलाने की घटनाओं के प्रबंधन के लिए कोष और मशीनें उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाना 'राजनीतिक मुद्दा' नहीं है और राज्यों को इस पर अंकुश लगाने की दिशा में काम करना चाहिए।

मद्देनजर प्रभावी है। तोमर ने राज्य सरकारों के साथ-साथ किसानों से ऐसी और तकनीक का उपयोग करने की अपील की। 'पूसा डिकंपोजर' के जरिये पराली को सामान्य तौर पर लगने वाले समय की तुलना में बेहद तेजी से खाद में बदला जा सकता है। यह किफायती होने के साथ ही मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में भी सहायक साबित होता है।

'पूसा डिकंपोजर' पर आयोजित एक दिवसीय समारोह को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा, करोड़ों रुपये और दो लाख मशीन उपलब्ध कराने के बावजूद पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि 2018-19 से, केंद्र सरकार ने चार राज्यों – पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा – को पराली जलाने की समस्या के प्रबंधन के लिए 3,138 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, जिसमें से 1,400 करोड़ रुपये से अधिक पंजाब को, 900 करोड़ रुपये हरियाणा को, 713 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को और 6 करोड़ रुपये दिल्ली को दिए गए हैं।

मंत्री ने दावा किया कि कुछ राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने अच्छा काम किया है। तोमर ने यह भी कहा कि उन्होंने पराली जलाने की स्थिति पर संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ एक सप्ताह पहले समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इस मामले पर और चर्चा करना चाहते हैं तो वह उनका स्वागत करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पराली जलाने की समस्या के एक प्रमुख मुद्दा बनने के साथ ही केंद्र, राज्यों और न्यायपालिका ने इस पर ध्यान दिया है और योजनाओं को लागू किया गया है।

सुपर सीएम और सात दलों के दबाव में हैं नीतीश सरकार: सुशील

पटना, एजेंसी। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नौकरी के नाम पर नीतीश सरकार को घेरा है। मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि एक 'सुपर सीएम' और सात दलों के दबाव में काम करने वाली महागठबंधन सरकार जब नियुक्ति संबंधी चार आयोगों के चंद शीर्ष प्रशासनिक पदों पर ही बहाली नहीं कर पायी, तब वह रिक्त पदों पर 4.5 लाख और नये पदों पर 5.5 लाख नियुक्तियां कैसे कर पाएगी? मोदी ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के तेजस्वी प्रसाद यादव के वादे का गुब्बारा पंक्चर होने वाला है। उन्होंने कहा कि जब नियुक्ति करने वाले चार आयोगों के शीर्ष प्रशासनिक पद ही आधे से ज्यादा खाली पड़े हैं और ये कछुआ चाल से काम कर रहें, तब बिहार सरकार 25 साल में भी 10.50 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाएगी। भाजपा नेता ने कहा कि नीतीश कुमार उन युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जिनकी बहाली प्रक्रिया एनडीए सरकार के समय ही पूरी हो चुकी थी।

सीओपी में विकासशील देश वित्त व तकनीक पर प्रतिबद्धता चाहेंगे: भूपेंद्र यादव

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचागत सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) में सीओपी के 27वें संस्करण से पहले कहा है कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर भारत जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संबंध में ₹कार्रवाई₹ के लिए विकसित देशों पर जोर देगा। उन्होंने कहा कि भारत इस बात पर भी जोर देगा कि वह उन कुछ देशों में से एक है जिसने पेरिस में निर्धारित 2015 के जलवायु लक्ष्यों को पूरा किया है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'लाइफ' आंदोलन के माध्यम से जलवायु न्याय और टिकाऊ जीवन

शैली पर जोर दिया गया है।

यादव ने बृहस्पतिवार को कहा, सीओपी27 को जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के मामले में कार्रवाई के लिए सीओपी होना चाहिए। यह हमारा समग्र दृष्टिकोण है। भारत इस बारे में स्पष्टता चाहेगा कि जलवायु वित्त के रूप में क्या कहा जा रहा है, चाहे वह अनुदान हो या ऋण या सब्सिडी। सार्वजनिक और निजी वित्त अलग होना चाहिए... इन मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है जिसका छह से 18 नवंबर के बीच मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजन किया जा रहा है।

अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में भाग लेंगे या नहीं। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के सम्मेलन में, विकसित देश विकासशील देशों को अपनी जलवायु योजनाओं को और तेज करने पर जोर दे सकते हैं। विकासशील देश जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक वित्त और प्रौद्योगिकी पर प्रतिबद्धता चाहेंगे।

एक अधिकारी ने कहा, यहां तक कि कुछ विकसित देश भीर विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के लिए प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर के मुद्दे को मजबूती से उठाने में भारत का साथ देंगे। यादव ने कहा कि विकसित देशों को न केवल पहले के जलवायु वित्त वादों को पूरा करना चाहिए, बल्कि नया सामूहिक मात्रात्मक जलवायु वित्त लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत वित्त संबंधी मुद्दे पर अधिक स्पष्टता पर जोर देगा।

भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ से महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी

नांदेड़, एजेंसी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही भारत जोड़ो यात्रा नांदेड़ जिले से सात नवंबर की शाम को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस यात्रा के लिए 'मैं चलूंगा' का नारा लगाया गया है। यात्रा के बारे में जानकारी एलईडी वैन, होर्डिंग्स, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन बन गया है।

सूत्रों ने बताया कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारा और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चल रहे इस अभियान को हर तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।

हिन्दुओं का घाटी में बसने का सपना साकार नहीं हो पा रहा: साहनी

जम्मू, मेट्रो मीडिया।

शिवसेना जम्मू कश्मीर ईकाई ने कश्मीर के हालातों में सुधार के लिए हिन्दू मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात को संतुलित करने और घाटी केअल्पसंख्यकों की हौसला अफजाई के लिए कश्मीर में जिला स्तर पर सुरक्षा कर्मियों एवं अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कालोनियां बनाने तथा फ्रीहोल्ड पलाट देने की मांग की है।

पार्टी मध्यवर्ती कार्यालय जम्मू में पत्रकारों से विशेष बातचीत करते हुए प्रदेश प्रमुख मनीश साहनी ने घाटी से पलायन और अल्पसंख्यकों पर जारी आंतकवादी हमलों पर गहरी चिंता जताते हुए, सरकार पर कश्मीर के हालात सुधारने एवं अल्पसंख्यकों

की सुरक्षा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। साहनी ने गत दिवस कश्मीर के अनंतनाग में प्रवासी मजदूरों पर हुए आंतकवादी हमलें की कड़ी निंदा करते आतंकवादियों को अपनी नापाक एवं कायराना हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी। इसके साथ ही लक्षित हमलों पर तत्काल लगाम के लिए सरकार से कड़े एवं ठोस कदम उठाने की मांग की है।

असंतोष

कंगना रनौत के मंडी सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा ने बढ़ाया गुस्सा, नेशनल सिख फ्रंट ने सरकार से की कई अहम मांगे

लगातार उपेक्षा किए जाने से सिख समुदाय में सरकार के प्रति बढ रहा है असंतोष

कुमार सतीश

जम्मू। विवादों में रहकर सुर्खियां बटोरने वाली अभिनेत्री कंगना रणौत के हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर हैं।

कंगना रणौत मंडी संसदीय सीट का चुनाव भाजपा की टिकट पर लड़ना चाहती हैं। जिसे लेकर सिख समुदाय में असंतोष पता चला है। जिसकी अहम वजह दिल्ली के बॉर्डरस पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चले किसान आंदोलन के दौरान सिख समुदाय के किसानों को लेकर कंगना रनौत द्वारा दिए गए घोर अपत्तिजनक बयान बताए गए हैं।

सिख समुदाय इस बात को लेकर भी हैरान है कि भाजपा के सिख नेता मनिंदरजीत सिंह सिरसा जोकि उस वक्त अकाली दल बादल से जुड़े थे और उन्होंने तब कंगना रनौत की आपत्तिजनक एवं विवादित बयानों को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, अब सिरसा ने कंगना रणौत पर चुप्पी क्यों साध रखी है। यहां सिख समुदाय का एक प्रमुख संगठन नेशनल सिख फ्रंट में कंगना रनौत प्रकरण पर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की रहस्यमय चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं।

नैशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन सरदार वीरेन्दर जीत सिंह का कहना है कि एक तो सिख समुदाय सरकार द्वारा उनकी मांगों की लगातार उपेक्षा किए जाने से नाराज है और अब पता चला है कि कंगना राणावत को हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी बना सकती है, से सिख समुदाय में भाजपा के प्रति और ज्यादा गुस्सा वह नाराजगी व्याप्त हो गई है।

फ्रंट का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पिछले साल कई भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया लेकिन उसमें पंजाबी भाषा को शामिल नहीं किया गया। जबकि पंजाबी भाषा को राजकीय भाषा बनाने के लिए लंबे अरसे से अपील की जाती रही है।

सिख समुदाय के अन्य प्रमुख मांगों में कश्मीर में निर्माणाधीन काजीगुंड टनल का नाम श्री गुरु तेग बहादुर टनल रखने, अल्पसंख्यक आयोग में सिख समुदाय का प्रतिनिधि नामजद करने, बंदा बहादुर की जम्मू के गंग्याल चौक पर आदमकद प्रतिमा लगाने, जेएण्डके पब्लिक सर्विस कमीशन में सिख समुदाय का एक सदस्य नामांकित करने, यहां हाईकोर्ट में सिख समुदाय से एक न्यायाधीश नियुक्त करने, विस्थापित कश्मीरी पंडितों को दी जा रही सहायता की तर्ज पर कश्मीरी सिखों को भी मदद दी जाए, जम्मू में 1989 में हुए सिख विरोधी दंगों के लिए गठित अंसारी कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, घाटी के चट्टी सिंह पुरा तथा महजूर नगर में हुए सिख नरसंहार की जांच रिपोर्ट का खुलासा हो तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर आए शरणार्थियों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए।

नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन सरदार वीरेंद्र जीत सिंह ने प्रदेश के कुछ स्कूलों में सिख समुदाय के बच्चों को कड़ा आदि पहनने पर तंग किए जाने की घटनाओं पर भी फौरन रोक लगाने की मांग की है।

काबिलेगौर है कि इस विषय को लेकर सिख समुदाय कई बार प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी का इजहार भी कर चुका है।

यहां सिख समुदाय के कुछ अन्य नेताओं का यदि कहना है कि यदि कंगना रनौत को भाजपा लोकसभा चुनाव में मंडी सीट से चुनाव मैदान में उतारती है तो सिख समुदाय उसका प्रबल विरोध करेगा।

Morning Glory Leasing and Finance Limited

CIN:L67120DL1984PLC018872 , Website: www.morninggloryleasing.in
Regd. Off: IRIS House 16 Business Centre, Nangal Raya, New Delhi-110046.
Email: morninggloryleasing@gmail.com, Ph: 011- 4711 9100

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2022 (₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	For the Quarter Ended on 30-09-2022	For the Quarter Ended on 30-06-2022	For the Quarter Ended on 30-09-2021	For the Half Year Ended on 30-09-2022	For the Half Year Ended on 30-09-2021
1	Total income from Operations	2.74	1.25	1.69	3.99	2.94
2	Net Profit for the period (before Tax & Exceptional items)	1.82	0.44	0.74	2.26	1.11
3	Net Profit for the period (before Tax after Exceptional items)	1.82	0.44	0.74	2.26	1.11
4	Net Profit for the period (after Tax after Exceptional items)	1.35	0.32	0.55	1.68	0.82
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	(88.59)	188.64	60.49	100.05	166.39
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹10/- each)	24.90	24.90	24.90	24.90	24.90
7	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (For continuing and discontinued operations) (Not Annualised)					
	1. Basic	(35.58)	75.76	24.29	40.18	66.82
	2. Diluted	(35.58)	75.76	24.29	40.18	66.82

NOTES :
1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their meeting held on 04th November, 2022. The unaudited financial results for the quarter and Six Months ended September 30,2022 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
2. The above is an extract of the detailed format of unaudited quarterly financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the unaudited quarterly results is available on the stock exchange websites.(URL-www.msei.in) and also on above mentioned Company's website at https://www.morninggloryleasing.in.
3. There is no change(s) in accounting policies which impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s).
4. Exceptional items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules.

For and on behalf of the Board of Directors of
Morning Glory Leasing and Finance Ltd
Sd/-
Rajesh Bagri
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 04th November, 2022